मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना सफल होगी

मुख्यमंत्री ने की सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से की गरीबों की मदद की अपील

जयपुर, 11 अगस्त 2011। श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल परिवारों के लिए 10 लाख आवास सुलभ कराने की योजना के तहत प्रथम किस्त के स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम को सफल बताते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि यह योजना बहुत कामयाब रहेगी। उन्होंने कहा कि अब तो जरूरत इस योजना की मोनिटरिंग की है और इसके लिए उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से अपील की है कि वे मिलकर इसकी मोनिटरिंग करें ताकि गरीब आदमी को कोई तकलीफ हो तो उसका मार्गदर्शन करें और उसकी सेवा करें। मुख्यमंत्री आज ओटीएस परिसर में आयोजित निर्मल ग्राम पुरस्कार समारोह में शिरकत करने के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री की बातचीत का ब्यौरा निम्न प्रकार से है -

प्रश्न फीडबैक कैसा रहा ?

मुख्यमंत्री: फीडबैक बहुत शानदार रहा। सब जगह सबने सहयोग किया। इसको हमने पार्टी लेवल पर नहीं किया, प्रोग्राम को। हमने आह्वान किया कि तमाम पोलिटिकल पार्टी को आकर के शुरू करना चाहिए और पूरा माहौल बना है राजस्थान भर के अंदर, लोग हजारों की तादाद में मीटिंगों में आये, भाग लिया। अब हम 2 अक्टूबर से जो दवाईयां फ्री कर रहे है। हर मरीज जो सरकारी अस्पताल में जायेगा उसका भी लोगों से बहुत बड़ा रेस्पोन्स मिला वहां गांव-गांव में और बाकी जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उसके ऊपर भी चर्चा गांवों में हुई। तो बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा।

अब तो उसकी मोनिटरिंग की जरूरत थी जो हम अपील करना चाहेंगे कि चाहे किसी भी पोलिटिकल पार्टी के लोग हों, वार्ड पंच है, सरपंच हैं, प्रधान, प्रमुख, मेम्बर, जिला परिषद, पंचायत समिति और दूसरे भी जन प्रतिनिधि हो सकते हैं। जो अपने हिसाब से काम करते हैं, एनजीओ वाले हो सकते हैं। सब मिलकर के मोनिटरिंग भी करें कि इसमें कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है गरीब आदमी को। उसको मार्गदर्शन करना है, सेवा करनी है, वो काम भी करें। इस रूप में मैं समझता हूं कि योजना बहुत ही कामयाब रहेगी। मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना को इसलिए लागू किया गया कि इन्द्रा आवास योजना की बहुत लम्बी लिस्ट है और इसके अन्तर्गत **60** हजार मकान प्रति वर्ष मिलते हैं।

योजना वहीं है उसको हमें इस हिसाब से पूरा करने में **22** साल लगेंगे अगर यही स्पीड रही तो। इसलिए **3** हजार **400** करोड़ रुपये का लोन लेकर के इसे प्रारम्भ किया गया। जिससे एक साथ में कम से कम इंदिरा आवास योजना के मकान मिला करके बाकी मकान मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना के हो जायेंगे। **10** लाख मकान बन जायें और शौचालय के लिए अलग से **3200** रुपये की योजना बनाई और उसके अंदर भारत सरकार ने निर्णय कर लिया कि नरेगा से हम उसको साथ मिला देंगे जिससे उसका और ज्यादा लाभ मिलेगा।

प्रश्नः इसके अंदर मर्ज हो गई है क्या इंदिरा आवास योजना **?**

मुख्यमंत्रीः मर्ज इसके अंतर्गत होगा तो जो मैटेरियल और लेबर कम्पोनेंट है उसका पैसा वहां से मिल जायेगा तो ये एक बहुत बड़ा, अच्छा निर्णय हो गया और हम चाहते हैं कि इस योजना के बाद जो गांव बचेंगे उनके लिए योजना लाएंगे। राजस्थान में हर व्यक्ति को पक्की छत मिले, पक्का मकान हो ये सपना देख कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।

प्रश्न **-** सीकर, झुंझुनूं में तो मुख्यमंत्री बीपीएल आवास में एक भी मकान का आवंटन नहीं हुआ**?**

मुख्यमंत्री: अच्छी बात है, अगर सीकर-झुंझुनूं के अंदर इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ही उनका कोटा जो बच गया है या जो कच्चे मकान है पूरे हो जायेंगे इसलिए उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अलवर वो जिला है जहां इस साल हम उनको मुख्यमंत्री बीपीएल आवास का जो कोटा देंगे उसी से उनका काम चल जायेगा। अगले साल उनको जरूरत

ही नहीं पड़ेगी। हम चाहते हैं ऐसी जरूरत और जिलों में नहीं पड़े। हर जिला कवर जो जाये। यही प्रयास सरकार का है। राजस्थान भर में कोई कच्चे मकान नहीं रहे, लोग पक्के मकान में ही रहें बस।